राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन-1999 /4107 डाक पंजीयन-म.प्र. / भोपाल / 371 / 2012-14

वर्ष-15,अंक-03 (बीस सालों से प्रकाशित) भोपाल, सोमवार 20 जनवरी 2014 मूल्य पांच रुपया

अबकी चोट करारी है, आप की चुनौती भारी है

कांग्रेस से मुक्ति पाने का सही समय

- आलोक सिंघई-

डेढ़ सौ साल पुरानी कांग्रेस एक बार फिर जता रही है कि हवा हवाई नेताओं के जमघट के बावजूद राजनीतिक चालें चलने में उसका कोई तोड़ नहीं है। बुढ़ा चुके ढांचे और और सत्ता के दलालों की फौज के बीच मौजूदा कांग्रेस जनता से पूरी तरह कट गई है। चंद सलाहकारों की कोटरी के बल पर आज की कांग्रेस जो नीतियां अपना रही है वे पूरी तरह से कांग्रेस की थानेदारी वाली संस्कृति की गुलाम हैं। प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह बार बार चिल्लाकर कह रहे हैं कि देश में थानेदारी वाला युग अब कभी नहीं आएगा लेकिन उनकी ही कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता बार बार खुद को देश का थानेदार बता रहे हैं। उनके भाषणों में झलकता दंभ और खुद को माईबाप बताने का दर्प बार बार बताता है कि वे आज भी खुद को अंग्रेजों की ही संतान मानकर चल रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर तो कभी विकास की बयार बहा देने के नाम पर हर बार कांग्रेस के नेता ये जताने की कोशिश करते नजर आते हैं कि वे देश के शासक हैं और देश की जनता उनकी शासित। सामंतवाद के खिलाफ खड़ी की गई कांग्रेस आज खुद सामंत की तरह बर्ताव कर रही है। यही कारण है कि पिछले 67 सालों के कांग्रेस के कुशासन के बावजूद देश आज तक सामंतवाद के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया है। कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और वह खुद परिवार वाद की जीती जागती मिसाल बन गई है। सामंतवाद भी इसी तरह कांग्रेस की छत्रछाया में पीढ़ी दर पीढ़ी अपना वजूद बचाए रहा है। कांग्रेस अपनी पुरातनपंथी नीतियों में इस कदर जकड़ी है कि वह अपनी गलतियां मानने तैयार ही नहीं है। परिणामस्वरूप वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि पंडित नेहरू के बोए जातिवाद, भाषावाद, सत्ता के केन्द्रीकरण,पाखंड भरी धर्मनिरपेक्षता के कारण दुनिया के अन्य मुल्कों की तुलना में केवल विकासशील देश ही बन पाया है। देश को श्रीमती इंदिरागांधी के दंभ जनित अनुत्पादक सरकारीकरण की मंहगी कीमत चुकानी पड़ी है। राजीव गांधी की कथित तकनीकी क्रांति की बेहिसाब कीमतें चुकाने के बावजूद आज तक हम देश के आम नागरिक को उसकी जरूरत के मुताबिक तकनीकी समाधान मुहैया नहीं करा सके हैं। परिवहन के नाम पर देश को वाहनों की जो बौछार झेलनी पड़ रही है उसके कारण हमारी मुद्रा कर्ज के जंजाल में उलझकर रह गई है। राजीव गांधी के पंचायती राज को ही तो देश की जनता ने कई राज्यों में लतियाकर सत्ता से बेदखल किया। आज की राहुल कांग्रेस ने बेरोजगारी दूर करने के नाम पर जो रोजगार गारंटी स्कीम चलाई वह भ्रष्टाचार का अड्डा तो बन ही गई साथ में देश से श्रम के महत्व को चकनाचूर करने वाली साबित हुई है। आखिर कब तक हम देश को प्रयोगों का अखाड़ा बने रहने देंगे। सवा सौ अरब लोगों का देश आज कई अरब रुपयों के कर्ज में डूबा हुआ है और आज की कांग्रेस इसे विकास की आंधी बताने में जुटी हुई है। विदेशी मुल्कों में जमा कराए गए धन की चमक से आखिर कब तक देश के लोगों को बहलाया जाता रहेगा। उधर कांग्रेस को हटाने के लिए विकल्प *(शेष भाग पेज 6 पर पढ़िए)*

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
जासूस बादशाह
भोपाल, सोमवार 20 जनवरी 2014

कांग्रेस और भाजपा में पहले आप की होड़

भारतीय जनता पार्टी खेमे से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी देश को कांग्रेस मुक्त करने की हुंकार भर रहे हैं। उधर कांग्रेस अपने भानुमति के कुनबे के साथ इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की लगाम थामने में जुटी है। इन दोनों दलों के बीच महासंग्राम भले ही अप्रैल महीने में हो लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी तेजी से अपना जनाधार बनाती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देश का आम आदमी दोनों राजनीतिक दलों की असफलताओं से ऊब गया है। कांग्रेस के विकल्पहीन कुशासन को बरसों झेलने के बाद जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में तैयार किया तो वो भी अपने दोयम दर्जे के नेताओं के कारण कांग्रेस की पिछलग्गू ही नजर आई। कांग्रेस की पूंछ पकड़कर चलने वाले भाजपा के नेताओं ने लीक से हटकर ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाया जो उन्हें देश के भाग्य विधाता का वो ओहदा दिला सके जो आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती वर्षों के राजनेताओं को प्राप्त था। ऐसे में देश के युवाओं ने चमत्कार दिखाते गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को ढूंढ़ निकाला। उन्हें आज भी उम्मीद है कि नरेन्द्र मोदी देश की विकास यात्रा को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। गुजरात की विकास यात्रा उनके सामने प्रमाण के रूप में मौजूद है। इसके बावजूद जिस तरह देश के राजनेता स्वयं पुरातनपंथी राजनीति के चक्रव्यूह से घिरे हैं उसी तरह देश की जनता भी तरह तरह के भ्रमों के कुहासे में फंसी हुई है। बरसों से ये मिथक राजनीति के गलियारों में गुंजायमान है कि देश पर राज करना है तो आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाईयों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। राजनीति के इसी बहु प्रचलित तर्क को आकाशीय वाणी मानकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देश का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां भी की जा रहीं हैं। भाजपा के दिग्गजों का अनुमान है कि जब भी मध्यम मार्ग के नेता की जरूरत महसूस होगी तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता भाजपा के पास दूसरा कोई नहीं होगा। सफलता, भाग्य, छवि, जनस्वीकार्यता जैसी किसी भी कसौटी पर श्री चौहान का कोई तोड़ नहीं है। भविष्य में जब कभी उनके शासन को रोजगार, वित्तीय प्रबंधन या सुशासन की कसौटी पर कसा जाएगा और असफलताओं को रेखांकित किया जाएगा,तब तक तो लोकसभा के चुनाव हो ही जाएंगे। इसके बावजूद भाजपा, आप पार्टी की विकास यात्रा से सबसे ज्यादा चिंतित है। दिल्ली में आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही बिजली के बिलों के माध्यम से हर नागरिक को नकद सौगात दी है। सबको पानी का वादा भी उन्होंने पूरा कर दिखाया है। बेहतर सुशासन की ये दो मिसालें हर नागरिक को लाभ पहुंचा रहीं हैं और लोकसभा चुनावों तक के लिए तो दिल्ली की जनता के आशीर्वाद में कोई कमी आने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। भाजपा के नेता ये समझ रहे हैं कि आप की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ सीधे तौर पर कांग्रेस को ही मिलना है। आप पार्टी हताश और हवाई दोनों ही किस्म के वोटों का डंपिंग बाक्स बन चुकी है और मीडिया उसका मार्गदर्शन बखूबी कर रहा है। जाहिर है हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली पर नए सिरे से विचार करना होगा। उनके नेताओं को सीना चौड़ा करके चलने वाली राजनीति छोड़कर जनता का जमीनी मार्गदर्शन करना होगा। दोयम दर्जे के फिलर नेताओं से मुक्ति पानी होगी और जमीनी नेताओं को अपना चेहरा बनाना होगा। इन दलों के नेताओं ने बदले हालात को नहीं समझा तो वे ध्यान रखें कि जिस तरह दिल्ली में पहले आप को विदा करने की होड़ ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया है उसी तरह आम चुनावों में भी आप का जादू कांग्रेस को समेटकर भाजपा की विकास यात्रा पर लगाम लगा सकता है।

क्या यह एक विचारधारा का अंत है?

--राजकिशोर--

भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेताओं की नई पीढ़ी अब सत्ता के शिखरों को शोभायमान कर रही है। बरसों से सांप्रदायिकता का आरोप झेल रही भाजपा को नई पीढ़ी के युवाओं ने दो टूक क्लीनचिट दे दी है। युवा पीढ़ी के साथ मुस्लिम और ईसाई मतदाता भी पहली बार भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस अब लगभग नेतृत्व विहीन हो गई है। केन्द्र सरकार की असफलताएं , कड़वे फैसले और बढ़ती मंहगाई ने कांग्रेस के प्रति मोहभंग का एलान कर दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस ने आप को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। कांग्रेस का यही राजनैतिक पैंतरा भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन गया है।

विचारधारा के अंत की घोषणा पश्चिम की ओर से आई है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरब भी उसके लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत को मैं इस तरह भी देखना चाहता हूं। दिल्ली भारत के आधुनिकतम शहरों में एक है।

आप के पास कोई विचारधारा नहीं है। इसके पलायनवादी जनक अण्णा हजारे के पास भी कोई विचारधारा नहीं है। खादी पहनने और कुछ अन्य लक्षणों से उनके गांधीवादी होने का भ्रम पैदा होता है। लेकिन अपने गांव में जिस तरह की डिक्टेटरी की स्थापना उन्होंने की है, वैसा गांधी जी भी अपने आश्रमों में नहीं करते थे। दूसरे गांधीवाद का लक्षण राजनीति से विरत रहना नहीं है। गांधी जी संत थे या संत बनना चाहते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका और भारत में, जहां भी रहे, आगे बढ़ कर जबरदस्त राजनीति की। अण्णा कहते हैं कि संविधान में राजनीतिक दलों का नाम नहीं है। लेकिन संविधान ने ही निर्वाचन आयोग बनाया है, जो चुनाव कराता है और राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। मैं अब मानता हूं कि दलविहीन राजनीति बेहतर है। लेकिन जब तक दल हैं, तब तक दलों के माध्यम से ही कुछ किया जा सकता है। फिर भी, कॉमनसेंस के आधार पर अण्णा हजारे ने कई अच्छे काम किए हैं।

'आप' का जन्म आंदोलन से हुआ है। लेकिन वह जीवन के सभी पहलुओं को समेटने वाला आंदोलन नहीं था। वह सरकारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। संसद से जन लोकपाल बिल पास कराना चाहता था। यह मांग अच्छी है, बहुत अच्छी है, यह कौन स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन केवल इससे भ्रष्टाचार राज का अंत हो जाएगा, यह मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। टायफायड के लिए पैरासिटामोल की गोलियां प्रस्तावित की जा रही हैं। फिर भी अरविंद केजरीवाल का रास्ता अण्णा हजारे से अच्छा है, क्योंकि अण्णा के यहां सिर्फ अनशन है, जबकि केजरीवाल उसके साथ-साथ तीर-कमान से भी लड़ना चाहते हैं। जनता अण्णा के पास जाती है, 'आप' जनता के पास जाता है। बहुत से अन्य लोगों की ही तरह हम भी उन्हें मुबारकबाद देते हैं।

एक कड़वी बात यह भी है कि 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का वास्तविक चरित्र क्या है, यह हम तभी जान पाएंगे जब यह पार्टी सत्ता में आएगी। विपक्ष में रह कर आदर्शवाद को निभाना सरल होता है, सत्ता में जाकर यथार्थवाद से बचना मुश्किल। अरविंद संपूर्ण विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आर्थिक विकेंद्रीकरण भी हो। दैत्य सरीखे बड़े-बड़े कारपोरेशनों के रहते हुए विकेंद्रीकरण का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं, जिनका जवाब 'आप' के पास नहीं है।

तो फिर आप की विशेषता क्या है? कॉमनसेंस की राजनीति। गांधी जी की एक अपनी विचारधारा थी। लेकिन उनके वही-वही काम सफल हुए जिनकी जड़ में कॉमनसेंस था। उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस में न विचारधारा बची न कॉमनसेंस। विचारधारा होना अच्छी बात है। लेकिन विचारधारा जब कॉमनसेंस को अपने घर से बाहर कर दे, तब संकट पैदा हो जाता है। सच पूछिए तो किसी भी विचारधारा का जन्म कॉमनसेंस की कोख से होता है। बाद में जब विचारधारा प्रबल हो जाती है, तब कॉमनसेंस अपनी जान बचा कर भाग निकलता है।

भारत के सभी दल, मतलब अधिकतर दल, विचारधारा से ही आए हैं। आजादी के पहले की कांग्रेस के पास भी विचारधारा थी। लेकिन जवाहरलाल और दूसरे राजनेता उसका भार न उठा सके। उन्होंने कॉमनसेंस का भी परिचय नहीं दिया। नतीजा सामने है। कम्युनिस्ट पार्टी तो अपनी विचारधारा के लिए ही जानी जाती थी। वह विचारधारा आज पहले से ज्यादा उचित और आवश्यक है। लेकिन अगर किसी दल ने सत्ता में जा कर अपने आदर्शों से सबसे ज्यादा समझौता किया है, तो वह कम्युनिस्ट पार्टी या पार्टियां ही हैं। कायदे से अगर कोई पार्टी अपनी विचारधारा से चिपकी हुई है, तो वह भाजपा है। लेकिन एक तो वह अपनी विचारधारा गैरों के सामने खोलती नहीं है, दूसरे वह सत्ता पाने के लिए उसके साथ तुरंत समझौता कर लेती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तभी बन सकी जब भाजपा ने अपने चार हठों को स्थगित कर दिया। इनमें से एक अनुच्छेद 370 को खत्म करना था। लेकिन आज फिर 370 पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब उससे फायदा होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने किसी भी विचार को न छुपाएगा न उसके साथ समझौता करेगा। लेकिन भाजपा के लिए सत्ता प्रधान है, विचारधारा नहीं। यह कॉमनसेंस को सिर के बल खड़ा करना है। क्षेत्रीय दलों के लिए तो उनका राज्य ही उनका देश है।

आप का जो कार्यक्रम अभी तक सामने आया है, उसके कुछ बिंदु ये हैं,- बिजली की दर कम करो, सब को पीने योग्य पानी दो, झुग्गी-झोपड़ीवालों के लिए घर बनाओ, स्कूलों की फीस कम करो आदि-आदि। ये सभी कॉमनसेंस की बातें हैं। इन मांगों को उठाने के लिए किसी भी विचारधारा को मानना जरूरी नहीं है। कोई अनपढ़ भी इन्हीं बातों को दुहराएगा। किसी अच्छी विचारधारा की मांग यह होगी कि दिल्ली में पांच-छह तरह के स्कूल नहीं होंगे, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसद से ज्यादा का फर्क नहीं होगा, दिल्ली की सड़कों पर एक ही स्तर की बसें होंगी, कोई भी कंपनी या दुकानदार दस या पंद्रह फीसद से ज्यादा मुनाफा नहीं लेगा, पांच सितारा होटलों को खत्म कर दिया जाएगा, मकानों के किराए कम कर उन्हें तकर्युक्त स्तर पर लाए जाएंगे आदि-आदि। वैसे तो ये भी कॉमनसेंस की ही बातें हैं, फर्क यह है कि किसका कॉमनसेंस कहां तक जाता है। गलत नहीं कहा गया है कि कॉमनसेंस की मुश्किल यह है कि वह कॉमन नहीं है।(जनसत्ता से साभार)

संसदीय परंपराओं का निष्पक्षता से निर्वहन होगा: डॉ.सीताशरण शर्मा

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा ने कहा है कि वे स्थापित संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने और संवारने का काम करेंगे। नए अध्यक्ष ने ये विचार उस समय व्यक्त किये जब चौदहवीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.सीताशरण शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह के अभिनंदन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विधानसभा परिसर के आडिटोरियम में ये समारोह विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही आयोजित किया था। समारोह में अभिनंदन के जवाब में डॉ.शर्मा ने कहा कि सभी लोग विनम्रता और निष्पक्षता से कार्य करें ताकि लोकतंत्र की प्रतीक हमारी विधानसभा अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी इसके हृदय हैं। सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों का काम विशिष्ट होता है। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री हों या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सबका मान सम्मान है। सबके मान का सम्मान होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि हम सब मिलकर विधानसभा की गरिमा को बढ़ाएंगे। कर्मचारी जो अपेक्षा रखते हैं वे भी पूरी की जाएंगी।

नेता प्रतिपक्ष श्री सत्यदेव कटारे ने कहा कि सचिवालय में पारिवारिक माहौल है। उन्होंने कहा कि यहां के कर्मचारी नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की कार्य प्रणाली के बारे

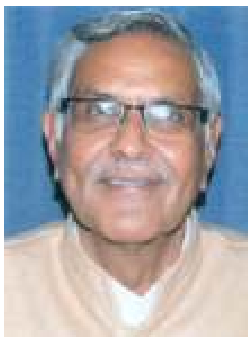

में बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करते हैं। इससे बेहद पेचीदा काम सरल हो जाता है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की याद ताजा करते हुए बताया कि जब वे पहली बार चुनकर आए थे तो विधानसभा के अधिकारियों ने उन्हें संसदीय परंपराओं की बारीकियां समझने में मदद की थी। उन्होंने किसी अधिकारी का नाम लिए बगैर कहा कि वे अधिकारी आज भी उसी कर्मठता से काम कर रहे हैं।

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा की परंपरा गौरवशाली रही है। यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया बहुत सहयोगात्मक रहता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की गाड़ी का एक पहिया विधायक हैं तो दूसरा पहिया यहां के कर्मचारी हैं।

विधानसभा के प्रमुख सचिव राजकुमार पांडे और सचिव भगवानदेव इसरानी ने उपस्थित गणमान्य राजनेताओं का पुष्पमालाओं से अभिनंदन किया। विधानसभा सचिवालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मो. युनुस खान एवं वरिष्ठ सदस्य श्री रामनारायण आचार्य ने नव निर्वाचित नेताओं को कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन उप सचिव पी.एन.विश्वकर्मा, ने किया। विधानसभा के सचिव भगवानदेव इसरानी ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रारंभ में विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री पांडे ने अध्यक्ष डॉ. शर्मा मुख्यमंत्री श्री चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्री कटारे और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ.सिंह को शाल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्रीगण, विधायक गण, पत्रकार और कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। विधानसभा सचिव श्री उमाशंकर रघुवंशी, अपर सचिव ए.पी.सिंह, और श्रीमती रचना त्यागी, विधानसभा के सूचना अधिकारी आर.एस.पाराशर सहित विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी और प्रदेश भर से आए गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।

कांग्रेस से जनता की चिढ़ को मोदी की सफलता मानने की भूल

शेष नारायण सिंह

पांच विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों के नतीजे आ गए हैं. उनका साफ़ सन्देश यह है कि कांग्रेस की हालत खस्ता है. वह उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण राज्यों से हटा दी गयी है. हिंदीभाषी क्षेत्रों में कांग्रेस का सफाया होना इस बात का संकेत है कि अब सत्ताधारी पार्टी के रूप में उसका फिर से स्थापित हो पाना दूर की संभावना है, क़रीब मुस्तकबिल में तो ऐसा होता नहीं दिखता. अब लोकसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू हो गयी है जो हर हाल में मई तक हो जायेगें. इसलिए इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के इतने सदस्य जीतकर नहीं आयेगें जिनके सहारे पार्टी सरकार बनाने का दावा कर सके.

परम्परागत रूप से राजनीति में लोकतांत्रिक और लिबरल मूल्यों के कस्टोडियन के रूप में कांग्रेस की पहचान होती रही है.यह भी माना जाता रहा है कि कांग्रेस के राज में भारतीय नागरिकों के सभी वर्गों को सम्मान मिलता रहा है. इसी खास पहचान के ज़रिये कांग्रेस कई राज्यों में और केन्द्र की सरकार के लिए चुनाव जीतती रही है. लेकिन गुजरात में कांग्रेस को पिछले कई वर्षों से हार का सामना करना पड़ रहा है. पहचान की राजनीति को अपनी मुख्य पहचान बना चुके वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से कांग्रेस को लगभग खत्म कर दिया है. व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ माने जाने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि कि भारतीय जनता के बड़े नेता यह मानने लगे हैं कि उनकी पहचान की राजनीति को केन्द्र के स्तर पर लागू करके केंद्रीय सत्ता को हासिल किया जा सकता है. बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को केन्द्र में रखकर इस बार चार विधानसभाओं के चुनाव का संचालन किया. जो नतीजे आये हैं उनको मीडिया का एक वर्ग नरेंद्र मोदी की जीत कहकर पेश करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सच्चाई इससे अलग है. जिन तीन राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है उन तीनों में बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व बहुत ही मज़बूत है और यह जीत उनके खाते में ही लिखी जानी चाहिए.

छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने पिछले दस वर्षों में ऐसे काम किये हैं जिसके कारण वे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाते हैं. उनकी योजनाएं लोकप्रिय हैं और उनके कारण उनकी पहचान राज्य के हर इलाके में है. यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को गिनाने का उद्देश्य नहीं है लेकिन इतना तय है कि वे राज्य में इतने लोकप्रिय हैं कि उनके नाम पर राज्य विधानसभा चुनाव बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है. छत्तीसगढ़ विधान चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक बार भी नहीं लगा कि वहाँ नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव है. बीजेपी के सबसे बड़े नेता के रूप में राज्य में रमन सिंह को पहचाना जाता है. रायपुर और उसके आसपास के इलाकों में राजनाथ सिंह की इज्ज़त है .भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में निश्चित पहचान है. कार्यकर्ताओं के बीच उनको अब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बराबर माना जाता है. लेकिन राज्य में वोट हासिल करने का सबसे अहम जरिया रमन सिंह ही हैं. अपने अखबार के लिए चुनाव अभियान की रिपोर्टिंग के दौरान जब बस्तर के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया गया तो साफ़ लग रहा था कि मुकामी विधायाकों से तो जनता बहुत नाराज़ है लेकिन चाउर वाले बाबा यानी रमन सिंह की लोकप्रियता हर जगह नज़र आती है. जहां भी नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया बस्तर के क़स्बों में भी उनके नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गयी. ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई जानता ही नहीं था.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता भी अपने राज्य में बहुत ज्यादा है .इस बार का चुनाव भी उनकी लोकप्रियता को केन्द्र में रखकर लड़ा गया. कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि उनके राज्य के भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बाना दिया जाए और उसी पिच पर उनको घेर लिया जाए. बीजेपी की कोशिश थी कि शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व के आस पास चुनाव को केंद्रित कर दिया जाय और उनकी लोकप्रिय को वोटों में तब्दील कर दिया जाए. राज्य में सरकार की तरफ से महिलाओं, नौजवानों और लड़कियों के लिए उन्होने इतनी लोकप्रिय स्कीमें चला रखी हैं कि आम आदमी की नज़र में उनको गिरा पाना बहुत मुश्किल है. शिवराज सिंह चौहान की पहचान को ही बीजेपी ने वोटों में बदल देने में सफलता पाई और वहाँ तीसरी बार सरकार बन गयी है. मध्यप्रदेश के चुनावों में भी नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं रही. यह अलग बात है कि मोदी की इमेज के प्रबंधकों ने मध्यप्रदेश में भी उनकी कई चुनावी सभाएं करवाईं लेकिन वहाँ चुनाव शुद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम पर लड़ा गया. नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे आदमी की बन गयी है जो मुसलमानों के बहुत खिलाफ है.

शायद यही वजह है कि राज्य के बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की बहुत सक्रिय भागीदारी के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनको मालूम था कि मुसलमानों के बीच में भी लोकप्रियता हासिल कर चुके शिवराज सिंह चौहान की छवि को नुक्सान होगा. हुआ भी यही. मोदी के कारण राज्य के वे मुसलमान मतदाता शिवराज सिंह के उम्मीदवारों के खिलाफ हो गए जो आमतौर से शिव मामा को वोट दिया करते थे. इसलिए बहुत ही भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि रमन सिंह की तरह शिवराज सिंह चौहान भी अपनी लोकप्रियता के कारण मध्यप्रदेश में बीजेपी को जीत दिला सके हैं. यह भी सच है कि बीजेपी के अंदर सक्रिय बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि शिवराज सिंह जीत जाएँ क्योंकि उनके तीसरा टर्म शुरू होने के मतलब यह होगा कि वे आर एस एस और कारपोरेट घरानों के चहेते नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय हो जायेगें. लेकिन आज शिवराज सिंह गुजरात से बड़े राज्य के तीसरे टर्म में जीते हुए मुख्यमंत्री हैं और उनकी लोकप्रियता किसी जाति या वर्ग विशेष के खिलाफ अभियान चलाने के कारण नहीं है .उनकी जीत में पिछले आठ वर्षों में किये गए उनके काम की स्वीकार्यता ही मुख्य फैक्टर है .

राजस्थान में बीजेपी की जीत में वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. उनको हटाकर ही अशोक गहलौत से गद्दी संभाली थी. अब उन्होंने वह सीट वापस ले ली है. राजस्थान में बीजेपी की जीत में कांग्रेस की असफलताएं मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं. अशोक गहलौत के पांच साल के कार्यकाल में राज्य के कांग्रेसी उनके खिलाफ काम करते रहे . अभी चार महीने पहले तक उनको हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की बात चलती रही. सी पी जोशी, सीसराम ओला, गिरिजा व्यास और सचिन पायलट ने हमेशा अशोक गहलौत को कमज़ोर साबित करने के लिए दिल्ली दरबार में अभियान चलाया. कांग्रेस की भी पता नहीं क्यों योजना थी कि आलाकमान ने अशोक गहलौत को चैन से शासन नहीं करने दिया. राजकाज चलाने में जो आज़ादी रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को मिली हुई थी, वह अशोक गहलौत को कभी नहीं मिली. इस तरह से साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान में बीजेपी की जीत में वसुंधरा राजे, सी पी जोशी, सीसराम ओला ,गिरिजा व्यास और सचिन पायलट का सबसे अधिक योगदान है. यहाँ भी नरेंद्र मोदी का कोई खास योगदान नहीं है. यह बात वसुंधरा राजे ने जीत के बाद कही भी कि जीत में सबसे ज़्यादा योगदान राजस्थान की जनता का है .

विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई दिल्ली में लड़ी गयी. राजधानी होने के कारण यहाँ के चुनाव के दूरगामी परिणाम होने वाले थे. इसीलिये नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव का ज़िम्मा खुद सम्भाला. बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किये जा रहे विजय गोयल को हटाकर उनकी जगह पर अपने उम्मीदवार डॉ हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया. दिल्ली शहर में कई चुनावी सभाएं कीं और जीत का भरोसा दिलाया . दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत ही अलोकप्रिय थीं. उनके खिलाफ बीजेपी जैसे मज़बूत संगठन को जीतने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा पाई और तीन बड़े राज्यों की चुनावी सफलता पर दिल्ली विधान सभा ने लगाम लगा दी. सही मायनों में दिल्ली विधान सभा का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव था लेकिन यहाँ पार्टी चुनाव में सरकार बनाने लायक सफलता नहीं ला सकी.

मिजोरम में कांग्रेस को जीत मिली है लेकिन 2014 के चुनावों में मिजोरम विधानसभा चुनावों का असर केवल उसी राज्य में पडेगा. राष्ट्रीय सन्दर्भ में उसका महत्व नहीं होगा ।

माफिया का घर बनी कांग्रेस तो लोगों ने ताक पर फेंका इतिहास

कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस बदलाव में नेताओं के बीच तालमेल के अभाव से कांग्रेस बिखरती जा रही है। इस बिखराव से कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। एक के बाद एक हार ने कांग्रेस के इस बिखराव को एक भटकाव में बदल दिया है। इस भटकाव के लिए पुराने नेता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गलत नीतियों को बता रहे हैं तो दूसरी ओर युवाओं को आकर्षित करने में भी पार्टी असफल हो रही है। आलम यह है कि लोग अब यह चर्चा करने लगे हैं कि कांग्रेस का यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव में इस पार्टी का आंकड़ा तीन अंकों को भी नहीं छू पाएगा। पर राहुल की सोच पर गंभीरता से नजर डालें तो कांग्रेस का नया चेहरा अपने पुराने चेहरे से कई गुना बेहतर होकर निखर सकता है। केवल जरूरत है इस बदलाव को समझने और उसके अनुरूप अपने को ढालने का।

कांग्रेस में ऐसे बदलाव को पुराने कांग्रेसी दिग्गज पचा नहीं पा रहे हैं। पुराने कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि राजनीति केवल उनके सोचे अनुसार ही चल सकती है। यह नेता यह भूल जाते हैं कि अब समय काफी बदल चुका है। मतदान का प्रतिशत 40-45 से बढ़कर 75-80 तक पहुंच गया है। इस प्रतिशत की बढ़ोतरी में युवा वर्ग का योगदान काफी है। वह भी ऐसे युवा का जो 18 से 25 वर्ष के हैं। इस युवाओं की सोच को समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। यह ऐसे युवा है जो किसी भी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने के माहिर होते हैं और इन्हें परिणामों की भी परवाह नहीं होती है। ऐसे युवाओं की ताकत को सही हो या गलत दिशा में मोड़ना आसान होता है। आधुनिक तकनीक ने चीजों की सर्वसुलभ उपलब्धता से यह युवा दूर दराज में घटी छोटी से छोटी बातों पर अपना उद्वेग को व्यक्त करने में देर नहीं करता है।

बलात्कार की एक घटना के दौरान राष्ट्रपति के दरवाजे तक हिला देना इसका छोटा सा उदाहरण है। ऐसे युवाओं को पार्टी के पुराने ढर्रों के चलते अपनी ओर लुभा पाना मुश्किल हैं। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने युवाओं की इसी शक्ति को पहचाना और उसे वह सपने दिखाए जो युवा चाहता है। यह अलग बात है कि युवाओं के साथ अगर अनुभव का संगम हो जाए तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा।

मोदी की बातों से युवाओं को लगता है कि गोधरा को लेकर कब तक जाप करते रहा जाए। अगर नई दिशा और नई ताकत दिखाने का कोई रास्ता बता रहा हो तो उसे क्यों न आजमाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। इसके पीछे कारण यह है कि युवा अपने तर्कों के सहारे और किताबों के अनुसार चीजों को हासिल करना चाहता है । पर इसमें जब दिक्कतें आती है तो युवा विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है। इसी विद्रोह के रंग को पहचान अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के सपनों को साकार करने का रास्ता बताया। केजरीवाल के इस रास्ते ने युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी। जिसका परिणाम है कि चंद समय में न केवल एक राजनीतिक दल बनाकर दिल्ली में पुराने राजनीतिक दलों को धूल चटा दी बल्कि पूरे देश में यह संदेश दे दिया कि रास्ता बनाने का ठान ले तो कोई आपको रोक नहीं सकता।

युवाओं को सांप्रदायिकता और जातीय राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। इसलिए अब यह ज्यादा दिन चलने वाली नहीं दिखती है। पर पुराने दिग्गज राजनीतिज्ञ इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वह उन्हीं पुराने रास्ते को राजनीति में इस्तेमाल कर सत्ता पर काबिज होने का कुचक्र रचते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक दलों को नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया। कांग्रेस भी इस पर सोचने के लिए मजबूर हो गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे बखूबी समझा। यही वजह है कि राहुल अब भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। चाहे वह उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला क्यों न हो। राहुल ने सरे आम यह कह डाला कि महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श सोसायटी घोटाले की जांच रिपोर्ट पर जो रवैया अपनाया वह ठीक नहीं है। हालांकि इस बार राहुल ने एक परिपक्व नेता का परिचय देते हुए अपनी पार्टी के नेताओं पर इतना रहम जरूर किया कि उनसे इस पर पुर्नविचार करने का आग्रह किया। सरकार को ही फाड़ कर फेंकने वाली बात नहीं कही।

हालांकि राहुल का यह कदम कई नेताओं को अच्छा नहीं लग सकता है। उन्हें लग सकता है कि पार्टी ऐसे नहीं चल सकती है। सत्ता में आने पर अपने आदमियों को भ्रष्टाचार का मौका मिलते रहने चाहिए। और यह मामला जब सामने आए तो उसे दबाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन यह नेता भूल गए है कि अब समय पहले वाला नहीं रहा। छोटी सी छोटी बात भी सेकेंडों में चहुंओर पहुंच सकती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए परसेप्शन बहुत मायने रखता है। मीडिया किसी का परसेप्शन अच्छा या बुरा करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में भ्रष्टाचार या कोई गैर कानूनी काम सरकार के लिए कब्र खोदने का काम कर सकती है। राहुल ने इन चीजों को भांप लिया है। अपनी पार्टी की शुद्धिकरण में राहुल जुट भी गए है। लेकिन वर्षो से जड़ जमा चुकी पार्टी के अंदर की इस गंदगी को साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर उसके दोयम दर्जे के नेता भी तो एक बड़ी बाधा हैं। राहुल को असफल करने के लिए उनकी पार्टी के नेता ही जी जान से लग गए हैं ताकि उनकी पुरानी दुकान चलती रहे। लेकिन ये नेता इस बात को भूल जाते हैं कि पार्टी सत्ता में रहेगी तभी उनकी महत्ता बनी रहेगी। राहुल के इस बदलाव भरे कदम का फिलहाल तो पार्टी को नुकसान नजर आएगा लेकिन भविष्य में इसी बदलाव की बदौलत कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। इतना जरूर है कि इस बदलाव से फिलहाल कांग्रेस में बिखराव की स्थिति बन गई है और इसका नुकसान कांग्रेस को अप्रैल-मई में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

मनमोहन सिंह को भरोसा, इतिहास उन्हें शाबासी देगा

पंकज झा

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अपने आख़िरी कार्यकाल से कुछ महीने पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए खुद के मूल्यांकन के लिए सबसे ज्यादा भविष्य के इतिहासकारों पर भरोसा जताना उचित ही था. आत्मविश्वास से डिगा हुआ व्यक्ति जैसे अपने आख़िरी राहत के रूप में इश्वर को याद करता है कांग्रेस जिस तरह हर कुकर्म के बाद धर्मनिरपेक्षता के बुरके में छुप जाती है वैसे ही एक कलंकित व्यक्तित्व के लिए यह उचित ही है कि वो भविष्य के इतिहासकारों पर सारा दारोमदार सौंप दें. अनुभव भी यही कहता है कि वाम पोषित इतिहासकारों ने ऐसे तत्वों को कभी निराश भी नहीं किया हो. चाहे हिंदुओं द्वारा गाय खाने की बात हो. वेद को गरडियों का गान कहने की या 'आर्य बाहर से आये' जैसे तथ्यों को स्थापित करने की. थके-हारे गिरोहों को वाम इतिहासकारों ने उनकी सुविधा के अनुसार हमेशा तर्क उपलब्ध कराया है. तो अगर 200 साल बाद भी वामपंथ ज़िंदा रहा तो निश्चय ही मनमोहन सिंह भी निराश नहीं होंगे. उनके उम्मीदों का इतिहास कुछ ऐसा लिखा जा सकता है-

आज से लगभग दो सौ वर्ष पहले इक्कीसवीं सदी की शुरुआत को इतिहासकार मनमोहन युग के रूप में याद रखते हैं. मनमोहन संवत की शुरुआत भी तभी से हुई थी. उससे पहले का कालखंड लगभग दशक भर भारत के लिए काला अध्याय सरीखा था. देश पर बाहरी हमला हो गया था. किसी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने (सेना)के साथ भारत पर कब्ज़ा कर लिया था. देश को कई टुकड़ों में बांट दिया गया था. उसके बावजूद अराजकतावादी अटल ने देश के तीन और टुकड़े कर दिए. चारों ओर भुखमरी और आतंक कायम था. ऐसे अंधेरे समय में एक नायक का देश में उद्भव हुआ. भारतीय उप-महाद्वीप को पहला और इकलौता ईमानदार व्यक्ति नसीब हुआ था. मनमोहन सिंह नामक इस क्रांतिकारी ने तब भारत की सत्ता सम्हाला था. घोड़े से तेज़ दौड़ कर वो दफ्तर जाते थे इसलिए उनका आवास रेसकोर्स रोड कहा गया. उन्होंने देश के एकीकरण के लिए दुनिया भर से कुछ विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायी. जिसमें गुलबुद्दीन हिकमतयार, मुस्तफा कमाल पाशा, बुतरस बुतरस घाली और यासिर खुराफात आदि प्रमुख थे. कुछ इतिहासकारों का भले यह दावा हो कि ये सारे विशेषज्ञ नाम मनमोहन के सत्ता सम्हालने से पहले दिवंगत हो गए थे लेकिन यह मानने का पर्याप्त कारण है कि इन लोगों के सहयोग से ही भारत का एकीकरण संभव हुआ था. चुकि मनमोहन सिंह खुद एक अर्थशास्त्री थे अतः यह तय है कि ये सभी लोग इन्हीं के शासनकाल में पैदा हुए थे, इसमें भगवा इतिहासकारों के अलावा और किसी को संदेह नहीं है. खैर.

भारत को पटरी पर लाने के बाद देश की बर्बाद पहचान को दुनिया भर में सुधारने के लिए ओलम्पिक की तर्ज़ पर मनमोहन ने एक कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया था. इस खेल में मेहमानों के लिए दस-दस (बिट करेंसी) (सौ स्वर्ण मुद्रा करीब) के बेड शीट आदि खरीदे गए थे. इतने के ही टाइल्स और गमले आदि की खरीदी कर देश का मान बढ़ाया था. समूची दिल्ली से भिखारियों गरीबों आदि को हटाया गया था ताकि दिल्ली बिलकुल मनमोहन सिंह की तरह दिखे. उस आयोजन के बाद ही भारत की पहचान दुनिया भर में कायम हुई. उससे पहले भारत को बस सपेरों के देश में रूप में जाना जाता था. हर नागरिक उससे पहले बे-ईमान था. उस खेल आयोजन के बाद ही भारत का खजाना भर गया. देश का बिजनेस बढ़ा. रूपये की कीमत में ज़ोरदार उछाल आया. भुगतान असंतुलन दूर हो गया. पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते हो गए और महंगाई आदि का खात्मा हुआ. नागरिकों में अपने प्रधानमंत्री के प्रति आदर और प्यार, एक भरोसे का संचार हुआ था. प्रचलित परंपरा के उलट सरदारों पर चुटकुले बनने भी उसके बाद बंद हो गए थे.

यह वही समय था जब भारत की सीमा रंगून तक पहुच गयी थी. वहां से टेलीफोन करने पर लोकल चार्ज लगता था. मनमोहन ने (टू जी) नाम का एक यंत्र विकसित किया था जिससे बात करने पर न केवल (जीरो लॉस)होता था बल्कि उलटे आमदनी भी होती थी. जब पश्चिम के देशों में लोग मोबाइल नाम के यंत्र के बारे में जानते तक नहीं थे उस समय ही मनमोहन सिंह ने वायरलेस पद्धति से बात करने की तकनीक को विकसित किया था. भारत में उस समय आम आदमियों के पास भी मोबाइल की सुविधा थी जब तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तक इस सेवा से वंचित थे. मनमोहन सिंह आकाश-

(शेष भाग पेज 7 पर पढ़िए)

चापलूसों और अवसरवादियों की भीड़ में गुम सी गई कांग्रेस

अखिलेश अखिल

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की संस्कृति पर सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का मानना है कि इसके पीछे पार्टी के अंदर चरणवंदना संस्कृति जिम्मेदार है। जब तक कांग्रेस इससे नहीं उबरेगी, तब तक जनता में उसकी छवि सुधरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी संस्कृति सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है? इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कांग्रेस हार से सबक लेकर अपना सुधार करेगी? या फिर चापलूस संस्कृति को जिंदा रखेगी?

हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को राजनीतिक दलों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक चाहे जिस तरह से परिभाषित कर रहे हों, लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस को इस हाल तक पहुंचाने में चाटुकार और दलाल टाइप के नेताओं की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। यूपीए की सहयोगी पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने जिस तरह बिना लाग-लपेट के कांग्रेस को झोलाछाप नेताओं की मंडली कहा है, वह कांग्रेस को सचेत करने के लिए काफी है। इसके साथ ही शरद पवार की यह बात उन सभी दलों के लिए भी सबक है, जो राजनीति तो करते हैं, लेकिन जनता से कोसों दूर रहकर देश-दुनिया के बदलते मिजाज को नहीं पहचान रहे हैं।

कांग्रेस में आज ऐसे चाटुकारों की भीड़ जमा है, जो खुद तो कहीं से चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन दूसरों की सीट तय करते नजर आते हैं। कांग्रेस में ऐसे दलालों और गांधी परिवार के प्रति झूठी आस्था दिखाने वाले लोगों की पूरी फौज खड़ी है, जो खुद नहीं लड़ती, लेकिन दूसरों को लड़वाकर अपनी रोटी सेंकती रही है। कांग्रेस की कार्यसमिति से लेकर तमाम कमेटियों की सूची को देख परख लीजिए, तो एक दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, जो जनता के बीच रहते हों, देश की नई पीढ़ी से कोई मतलब रखते हों और जो गांव, समाज और देश की समस्या से कोई सरोकार रखते हों। ऐसा ही हाल कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों का है। कांग्रेस के उन प्रभारियों का तो हाल देखिए, जो प्रदेश की राजनीति को अपनी अंगुली पर नचाते फिरते हैं। इन नेताओं में अधिकतर वही लोग मिलेंगे, जो कभी चुनाव जीतकर नहीं आए। केवल चाटुकारिता के दम पर कांग्रेस के ऑफिस में विराजमान रहते हैं और टीवी से लेकर अखबारों में झूठे बयान देकर लोगों को बरगलाते नजर आते हैं।

इस पूरे खेल में इन चाटुकारों की नीति होती है कि सोनिया और राहुल पर कुछ न बोलें। ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही हैं कि चार राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के भीतर इस बात पर मंथन हो रहा है कि क्यों न राज्य के प्रभारियों से लेकर अध्यक्षों को पद से हटा दिया जाए? संभव है कि कांग्रेस में ऐसा हो भी, लेकिन इससे भला क्या होगा? क्या जमीनी नेताओं को तरजीह मिलेगी? क्या कांग्रेस के लोग आम जनता के बीच होंगे? क्या कांग्रेस की नीतियां बदलेंगी? क्या कांग्रेस के हवाई नेता बाहर होंगे? क्या सोनिया और राहुल की चरणवंदना बंद होगी? क्या कांग्रेस अमीरों की पार्टी से विमुख होकर गरीबों और आमजनों की पार्टी बनेगी? कांग्रेस को इन तमाम बातों पर गौर करना है और याद रखिए कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, तो उसका मर्सिया भी जल्द ही पढ़ दिया जाएगा।

हद तो यह देखिए कि हिंदी पट्टी के चार राज्यों में कांग्रेस के जमींदोज हो जाने के बावजूद चाटुकार और दलाल नेताओं ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस जब-जब हारती है, तब-तब अगले चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है। चाटुकारों के इस बयान में दम भी है, लेकिन असली सवाल है कि क्या देश की जनता का मूड और मिजाज अब वही है, जो पहले हुआ करती थी। बदलते परिवेश, बदलती राजनीति और देश में नए जमाने के 40 करोड़ से ज्यादा युवाओं को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली कांग्रेस जैसी पार्टी से अब कोई लेना-देना नहीं रह गया है। इस युवा पीढ़ी को न तो देश की आजादी की लड़ाई से कोई मतलब है और न ही वंशवादी राजनीति से कोई सरोकार। इस पीढ़ी में उस जमींदारी प्रथा वाली राजनीति, एक ही परिवार के इर्द-गिर्द घूमती राजनीति, जनता से विमुख होते नेता, जनता को बेचारी समझने वाले लोगों के प्रति बेतहाशा आक्रोश है और इस पूरे खेल को वह पीढ़ी एक राजनीतिक गुलामी के तौर पर देख रही है। आजाद देश में आजादी की दूसरी लड़ाई इंदिरा शासन के विरोध में जब 1977 में संपूर्ण क्रांति के रूप में लड़ी गई, तब भी आज जैसे ही हालात थे। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके 30 साल बाद 1977 में कांग्रेस के कुशासन और इंदिरा गांधी की जनविरोधी करतूतों से आजीज आ चुकी जनता ने सत्ता पलटने में देर नहीं लगाई।

तमाम तरह के राजनीतिक गुणा-भाग के बावजूद अभी कांग्रेस के मर्सिया पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वक्त के साथ कांग्रेस के चाल, चरित्र और चिंतन में बदलाव नहीं आया और गांधी परिवार से कांग्रेस आगे नहीं निकली, तो इसके लिए फातिहा पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भले ही मोदी देख रहे हों लेकिन उसे साकार करने का काम खुद कांग्रेस के चाटुकार कर रहे हैं।

याद रखिए इंदिरा की सत्ता को भी इसी युवा वर्ग ने पलट दिया था। ये वही युवा वर्ग था, जिसने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, लेकिन आजादी के 30 सालों को या तो जिया था या फिर आजादी के बाद के सालों में जन्म लिया था। इसी नई पीढ़ी ने सब कुछ बदलने का संकल्प लिया और बदल भी दिया। तब केवल कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और इंदिरा के विरुद्ध लहर। इस लहर में कांग्रेस पराजित हो गई और इंदिरा की भारी हार हुई। अब 77 के आंदोलन के 36 साल बाद फिर जनता के राडार पर कांग्रेस आ गई है। इसे आप केंद्र सरकार विरोधी लहर कहें या फिर सोनिया विरोधी, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस विरोधी यह लहर आगामी लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। एक बात और है कि जनता का यह विरोध अब केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। अब विरोध की धार पर वह भाजपा भी है, जिसकी आयु अब 30 साल की हो गई है। तय मानिए, जिस तरह से आजादी के 30 साल बाद 77 में कांग्रेसी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका था, लगभग वही हाल अब भाजपा का भी होना तय है। राष्ट्रीय स्तर पर संभव है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर का फायदा भाजपा को मिलता दिखे, लेकिन जिस तरह से 'आप' जैसी ताकतें देश के कोने- कोने से उभरेंगी। वंशवाद, लूट और भ्रष्टाचार पर टिकी पार्टियां जनता का निवाला बनती रहेंगी। कांग्रेस के भविष्य की राजनीति पर और भी बातें करेंगे, लेकिन यहां कुछ उन चाटुकारों की चर्चा की ली जाए, जो कांग्रेस को रसातल में ले जाने के लिए बेताब हैं।

राजनीति करना और बयान देना दोनों अलग-अलग बातें हैं। राजनीति, रणनीति और कूटनीति से की जाती है और बयान राजनीति का मात्र एक हथकंडा भर होता है। बयान सच भी हो सकता है और राजनीति से प्रेरित भी। आप देश की राजनीति के इतिहास में चले जाइए, तो पता चलेगा कि देश में सत्ता की राजनीति करने वाले लोग कभी बयानों की राजनीति नहीं करते। बयानों की राजनीति असली राजनीति के सामने ठहर भी नहीं पाती। बयानों की राजनीति असली राजनीति की साया भर होती है और संभव है कि इसे समझना सबके बूते की बात भी नहीं हो। यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सरकार के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक बयान सोनिया गांधी को देश की मां तक कह डाला। हालांकि इस बयान में किसी की इज्जत नहीं उछाली गई है और न ही किसी का अपमान ही किया गया है। संभव है कि खुर्शीद के इस बयान से देश की जनता का कोई सरोकार न हो, लेकिन इस बयान ने खुर्शीद की चाटुकारिता को सामने ला दिया है। इसी खुर्शीद ने कुछ महीने पहले अपने एक साक्षात्कार में कांग्रेस को दिशाहीन कहने की गलती कर दी थी। इस बयान का कांग्रेस के अन्य चाटुकारों ने विरोध किया और अंत में खुर्शीद को अपने कहे के लिए माफी तक मांगनी पड़ी थी। लेकिन याद रखिए, कांग्रेस की चाटुकारिता करने वाले खुर्शीद कोई पहले आदमी नहीं हैं। जब इंदिरा गांधी का राज था, तब भी कांग्रेस में चाटुकारों की बड़ी फौज खड़ी थी। उस समय भी देवकांत बरुआ जैसे लोग थे, जो 'इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा' कहकर चाटुकारिता करते फिर रहे थे और कांग्रेस रसातल की ओर जा रही थी। आज फिर वही इंदिरा वाली संस्कृति सोनिया के सामने है। चार राज्यों में कांग्रेस की हार को लेकर कांग्रेस के भीतर मंथन जारी है। लेकिन मंथन फिर वही जड़विहीन लोग कर रहे हैं, जिनका जनसरोकार से कोई वास्ता नहीं है।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस नाकामी का श्रेय लेने को कोई भी तैयार नहीं है, बल्कि सभी एक-दूसरे के माथे ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। जरा मणिशंकर अय्यर और सत्यव्रत चतुर्वेदी सरीखे नेता की बातों पर गौर कीजिए। 2009 का लोकसभा चुनाव मणिशंकर अय्यर हार चुके हैं और अभी वे मनोनीत कोटे से राज्यसभा के सदस्य हैं। रही बात सत्यव्रत चतुर्वेदी की, तो वे भी मध्य-प्रदेश कोटे से राज्यसभा सदस्य ही हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही जनाधारविहीन नेता हैं। न तो ये अपनी सीट जीत सकते हैं और न ही पार्टी की जीत में योगदान दे सकते हैं। कांग्रेस की विडंबना यही है कि सत्ता में दस जनपथ के आस-पास ऐसे ही लोगों का वर्चस्व रहा है, जो बिना रीढ़ के नेता हैं। जो जितना कमजोर और जड़विहीन, कांग्रेस के गलियारों में वह उतना ही मजबूत। मिसाल के तौर पर अहमद पटेल को ही लिया जाए। अहमद भाई उसी गुजरात से आते हैं, जहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। सोनिया के राजनीतिक सलाहकार के गृह-प्रदेश गुजरात में कांग्रेस काफी दयनीय हालात में है। चाणक्य कहे जाने वाले अहमद भाई अपने ही राज्य में लगातार मात खाते जा रहे हैं। अहमद पटेल कांग्रेस की लगातार हार के लिए अपने को दंड दे सकते हैं? जो अहमद पटेल आज तक लोकसभा से लेकर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सके, वह भला चुनाव की राजनीति कैसे कर सकते हैं? और राजनीति करते भी हैं, तो अपनी राजनीतिक हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? इसी अहमद पटेल से एक और सवाल है कि क्या वे अपनी ही पार्टी के नेताओं से मिल पाते हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजनीतिक सचिव होने के नाते उनका पहला काम तो यही था कि वे देश के राजनीतिक मिजाज को पहचानते और सोनिया गांधी तक देश की असली तस्वीर रखते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए?

उस दिग्विजय सिंह को क्या कहेंगे जिसने अपने प्रदेश में तो कांग्रेस का कबाड़ा किया ही देश भर में उसे नफरत का प्रतीक बना डाला। अजीत जोगी को क्या कहेंगे? उस शकील अहमद को आप किस श्रेणी में रखेंगे? उस गुरुदास कामत की राजनीति को आप क्या कहेंगे? इन्हें नेता कहा जाए या फिर दलाल या चाटुकार? प्रदेश के तमाम अध्यक्षों को आप क्या कहेंगे, जो अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस को जीत दिलाने में असफल हैं। आज की हालत यह है कि इस देश में डंके की चोट पर दस आदमी भी कांग्रेस के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के नेताओं से कार्यकर्ता की मुलाकात और बात नहीं होती। कार्यकर्ता से जनता की मुलाकात और बात नहीं हो रही है। गौर करके देखिए, कांग्रेस में आज अधिकतर नेता 60 से 70 बरस के हो गए हैं, जो वोट की राजनीति पुराने ढर्रे पर कर रहे हैं, जबकि आज की पीढ़ी तमाम पुराने नेताओं से अलग सोच रख रही है। राहुल गांधी युवाओं की राजनीति करने की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव के समय इन्हीं बूढ़े नेताओं के खेल के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। 125 साल पुरानी इस पार्टी को पीवी नरसिम्हा राव सहित अगर मनमोहन सिंह ने कमजोर किया है, तो दस जनपथ का भी कम योगदान नहीं रहा है। दस जनपथ ने कभी एक मजबूत नेतृत्व आस-पास पनपने नहीं दिया। यदि किसी नेता का कद दस जनपथ से ज्यादा बढ़ा, तो उसके पर तुरंत कतर दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश जीता-जागता मिसाल है। आखिर जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही, तो बनना चाहते थे। आज उन्हें नकार कर कांग्रेस वहां बदतर हालात में पहुंच गई है। कहने की जरूरत नहीं कि दस जनपथ के इर्द-गिर्द आज चाटुकारों का जमावड़ा है। और जो लोग आज राहुल गांधी को नकार रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि कभी स्वर्गीय इदिरा गांधी को भी लोहियावादियों ने 'गूंगी गुड़िया' की उपाधि दी थी। उसी गूंगी गुड़िया ने लोहिया समेत तमाम नेताओं की बोलती बंद कर दी थी।

अरुण यादव को अध्यक्ष बनाने से फिर लौटेगी संगठन की बुलंदी

भोपाल। खंडवा से सांसद अरुणयादव को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। लगातार साढ़े चार साल तक प्रदेश कांग्रेस की कमान थामने वाले स्व. सुभाष यादव के इस नए अवतरण से प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आम चुनाव के पहले पिछड़े वर्ग के इस युवा नेता के हाथों में कांग्रेस की बागडोर थमाकर कांग्रेस आलाकमान ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की हार का लांछन झेल रहे जनता के खलनायक दिग्विजय सिंह के लिए भी ये कदम चौंकाने वाला है।

कांग्रेस से मुक्ति पाने का सही समय

(पेज एक का शेष भाग)

के तौर पर उभरी भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस के चंगुल में फंस गई है। भाजपा में शीर्ष पदों पर ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों की घुसपैठ करा दी गई है जिन्होंने भाजपा को पपलू पार्टी बनाने का अभियान चला रखा है। जब देश की तरुणाई गुजरात के विकास माडल को समझकर नरेन्द्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने चल पड़े हैं तब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के करीब जमे बैठे कुछ लोग दोयम दर्जे के नेताओं को प्रश्रय देकर पार्टी का बधियाकरण करने की कोशिशें कर रहे हैं। वे भाजपा को कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बनाने में जुटे हैं। जैसे कभी अंग्रेजों ने भारतीय दिखने वाले कांग्रेसी पिछलग्गुओं को अपनी नीतियों के बचाव में खड़ा किया था उसी तरह अब कांग्रेस के दिग्गज भाजपाई दिखने वाले अपनी नीतियों के रक्षकों को खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मौजूदा नीतियों को ही बचाने में शाक एब्जार्बर का काम कर रही है। विचार करें तो आप भी कांग्रेस मुक्त भारत की नीति पर अमल करने निकल पड़ेंगे। कांग्रेस से मुक्ति का मतलब समाज को धड़ों में बांटने वाली विचारधारा से मुक्ति है। देश को जोड़ने वाली विचारधारा की ओर अग्रसर होना है। इस बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। देश टूटेगा नहीं क्योंकि देश एक बार फिर खड़ा हो रहा है।

मनमोहन सिंह को इतिहास से शाबासी का भरोसा

(पेज चार का शेष भाग)

पाताल–और जमीन तीनों के (जानकार) थे. कोयला आदि खोदवा कर उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा. विरोधियों ने उन पर कोयला घोटाला से लेकर टू जी और कोमनवेल्थ खेल घोटाला आदि का आरोप लगाया था. कैग नाम की संस्था भी खिलाफ में रपट देने लगी थी. कोर्ट तक विपक्षी साज़िश का हिस्सा बन गया था. वहां भी उन पर सारे अपराध साबित हो गए थे. लेकिन मनमोहन सिंह झुके नहीं. उन्होंने सारे आरोपों का सामना किया और खुद को उन आरोपों से खुद ही क्लीन चिट दे दिया. वे बेदाग़ बरी हुए थे.

मनमोहन सिंह अपने पूर्ववर्ती बहादुरशाह जफर से भी बड़े शायर थे. देश की रक्षा के निमित्त वे सुन्दर–सुन्दर शायरियों की रचना करते थे. वे दूसरों के शेर भी इतने आत्मविश्वास के सात पढते थे कि बिलकुल ऐसा लगता था मानो उनके खुद के बनाए हों. एक बार देश पर आये किसी संकट के समय उन्होंने एक अद्भुत शेर की रचना कर सवाल पूछने वालों को बेनकाब किया था. उनके उस शेर के कारण ही दिल्ली में दिल्ली में निर्भया समेत कई सवालों तक की आबरू बचना संभव हुआ था. दुश्मन उसके बाद इस डर से कोई सवाल उठाने से भी कांपने लगे थे कि कहीं फिर से ऐसा कोई खास ऐतिहासिक शेर न सुनना पड़ जाए.

मनमोहन सिंह के समय ही देश में मोदी नाम का एक आतंकी पैदा हुआ था. जिससे साबरमती के मैदान में लंबी लड़ाई हुई. अंततः मल्लयुद्ध में उसे परास्त कर मनमोहन ने देश को (आज़ाद) कराया था. हालांकि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि साबरमती नाम का कोई मैदान नहीं था बल्कि उस नाम से एक नदी थी. कुछ भगवा इतिहासकारों का कहना है कि इसी नाम की नदी के तट पर कोई बिना खड्ग–बिना ढाल वाला संत भी पैदा हुआ था. लेकिन चुकि मनमोहन सिंह उस समय के बड़े अर्थशास्त्री रहे थे अतः यह हो ही नहीं सकता कि वे पानी में मल्लयुद्ध करें. अतः इससे यह साबित होता है कि साबरमती का वो मैदान ही रहा होगा जहां मोदी को परास्त कर उन्होंने भगवा आतंक का खात्मा किया था.

अपने लंबे और यशस्वी कार्यकाल के उपरान्त देश को (सोनिया की चिड़िया) बना कर अंततः मनमोहन वानप्रस्थ को निकले. उस समय रॉबर्ट वढेरा नाम का देश का एक बड़ा किसान हुआ करता था जिसके साले ने बाद में भारत के प्रधानमंत्री का पद सम्हाला. तब देश के सीईओ को (प्रधानमंत्री) ही कहा जाता था. निष्पक्ष प्रेक्षकों के अनुसार मैकाले और माउंटबेटन के बाद पहली बार भारत को मनमोहन के रूप में एक देशभक्त शासक मिला था. इनका शासन काल वास्तव में भारत में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने लगा है. आज यहां लोग सुख चैन की बंसी बजा रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड का भाव लेकर चलने वाली अपनी पार्टी के लिए जी जान न्यौछावर करने वाले रणबांकुरों को साथ लेकर वह देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाने चल पड़ी है। उम्मीद है कि आजाद हिंदुस्तान के ये शासक हर नागरिक की गरीबी जरूर दूर कर देंगे।

इस बार जरा तूफानी हैं गैर कांग्रेसवाद की हवाएं

गैरकांग्रेसवाद (नरेन्द्र मोदी के शब्दों में कांग्रेस मुक्त भारत) एक बार फिर दस्तक दे चुका है. विभिन्न राज्यों के चुनावी नतीजे यही संकेत कर रहे हैं. कांग्रेस के हौसले पस्त हैं. हाल के सालों में बीजेपी की जो डाउनस्लाइड देखी गई वो थमी है और इसके उपर जाने के आसार बन रहे हैं. कांग्रेस की घटत और बीजेपी की बढ़त उन जगहों पर हुई है जहां कांग्रेस ब्रांड सेक्यूलरिस्ट ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये दंगों से उपजे पोलराइजेशन का कमाल है।

दिल्ली में एक बड़ा सबक जेडीयू को भी मिला है। नीतीश और उनका पूरा मंत्रिमंडल कई दिनों तक दिल्ली में कैंप किए रहा। आम आदमी पार्टी से ज्यादा खर्च और केंपेन के बावजूद जनता ने उन्हें खारिज किया है। संदेश यही कि कांग्रेस के साथ नीतीश जाएंगे तो नकारे जाएंगे। दिलचस्प है कि दिल्ली में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और वहां वोटर हैं। बिहारियों का ये मानस चौंकाता है। बिहार के अधिकांश लोग लालू एरा के शुरूआती चरण में ही दिल्ली चले गए थे और इनमें कांग्रेस के लिए वो तल्खी नहीं रही जो बिहार में रह रहे उनके परिजनों की रहती है। बावजूद इसके नीतीश की महत्वाकांक्षा को पर लगने का मौका नहीं दिया दिल्ली के लोगों ने। नीतीश की पराजय इस मायने में भी है कि वो मायावती की बीएसपी वाली परफारमेंस (दिल्ली के पिछले चुनाव में) तक नहीं पहुंच सके।

महंगाई का डंक और ऊपर से कांग्रेसी नेताओं के जले पर नमक छिड़कने वाले बयानों का हिसाब चुकता करने वाली जनता ने केजरीवाल को सर आंखों पर बिठाया है। कांग्रेस के अहंकार को शिकस्त मिली है। अप्रत्याशित और पॉलिटिकल क्लास को डराने वाले आंदोलनों का गवाह रही दिल्ली की जनता ने उन आंदोलनों को निर्ममता से कुचलने की कांग्रेसी निरंकुशता का जवाब भी दिया है। न जाने राजबाला की आत्मा कैसा महसूस कर रही हो। जो पॉलिटिकल अनालिस्ट उन आंदोलनों को मीडिया का क्रिएशन बता कर खारिज कर रहे थे उन्हें भी सीमित संदर्भ में वोटरों ने जवाब दिया है। निश्चय ही केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को नया नजरिया और नई ग्रामर दिया है। ये आंदोलन के समय से लेकर चुनावी समर के नतीजों तक में उन्होंने दिखाया है। सभी जानते हैं कि अन्ना को केजरीवाल की मेहनत से वो शोहरत मिली जिसने उनमें गांधी का अक्स ताकने के लिए आज की युवा पीढ़ी को ललचाया। राष्ट्रीय फलक पर अन्ना सबके चहेते बने। नतीजों के बीच केजरीवाल को जो पॉलिटिकल पंडित सेहरा देने को मजबूर हुए हैं वो कल तक आम आदमी पार्टी को नकारते रहे। आज भी ये वर्ग यही साबित करने पर तुला है कि आप ने सेक्यूलर स्पेस को मजबूती दी है। बावजूद इसके कि आप राष्ट्रवादी स्पेस की शक्ति है। यही लोग आरएसएस से आप के लिंक को खोजते रहते थे। इस बात को छुपाते हुए कि आंदोलन के समय अन्ना के लोगों को माओवादियों ने भी ऑन रिकार्ड समर्थन दिए थे।

दिल्ली सिटी एस्टेट जैसा है। संभव है लोकसभा चुनावों के समय केजरीवाल ग्रामीण भारत में वैसा चमत्कार नहीं दुहरा पाएं। पर राजनीति को बदलने लायक मिजाज लोगों में विकसित जरूर कर दिया है। उनके आलोचक कहते कि मुद्दों के आधार पर लंबी पारी नहीं खेली जा सकती। यानि विचारधारा या फिर वैचारिक आधार होना जरूरी है...आप के नेताओं पर यकीन करें तो उनका वैचारिक आधार ग्राम स्वराज की कल्पना को नए संदर्भ में परिभाषित करना है। ग्राम स्वराज शब्द पर फोकस पड़ेगा और ये कांग्रेस को डराएगा जबकि बीजेपी को सचेत रखेगा। सोनिया नतीजों के बाद ये कहने को मजबूर थीं कि सही समय पर पीएम उम्मीदवार का एलान होगा तो राहुल ने आप से सबक सीखने की शालीनता दिखाई। आप के कारण राजनीति का तात्विक अंतर बीजेपी को दिल्ली की तरह (हर्षवर्द्धन को सीएम उम्मीदवार बनाने जैसे कदम) मजबूर करेगा कि ये – पार्टी विद अ डिफरेंस – की अपेक्षाकृत ज्यादा स्वीकार्य छवि की ओर लौटे। गडकरी ने आठ दिसंबर की शाम जब कहा कि बीजेपी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। तो एक अर्थ में ये आप की राजनीति के असर को स्वीकारना भी है...बरना कांग्रेस की नापसंदगी का फायदा तीसरे मोर्चे का समूह भी उठा ले जाएगा।

शरीर को निरोगी बनाए 'रसाहार'

जनजातीय समुदाय के लोग जड़ी-बूटियों को तोड़कर, उसे पीसकर उसका उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, लेकिन अब यह चलन शहर की ओर भी बढ़ने लगा है, कई तरह की जड़ी-बूटियों का उपयोग शहरी लोग भी करने लगे हैं। चूंकि जड़ी-बूटिंयों का स्वाद खाने में अजीब लगता है, इसलिए शहरों में इसे पीसकर इसका रस निकाला जाने लगा है। जो आसानी से मरीज के शरीर में पहुंचकर अपना असर दिखाता है। इसी को शहरी भाषा में रसाहार प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाने लगा है। इसमें रोगी को केवल आहार सम्बन्धी नियमों को दृढ़ता से पालन करते हुए कुछ भिन्न-भिन्न स्वाद वाले रस पीने पड़ते हैं। इसी मुद्दे पर रसाहार शोध समिति की परामर्शदात्री पूर्णिमा दाते से खास बातचीत की गई। उनसे रसाहार के उपयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ अंश-

दाते ने बताया कि सुबह का रसाहार करने की प्रक्रिया रोगी कस कर थाम ले तो उसके दिन आसान होते जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत में अभी जो प्राकृतिक चिकित्सा चलन में है, वह जर्मनी से आई है। जबकि भारत में यदि एक लाख वनौषधियां हैं, तो जर्मनी में मुश्किल से एक हजार होंगी। फिर जर्मनी के प्राकृतिक चिकित्सक उन वनौषधियों के प्राकृतिक उपयोग हमें कैसे सिखा सकते हैं। परिणामस्वरूप रसाहार के रूप में केवल फलों, सब्जियों और गेंहू के जवारे का ही उपयोग प्रचलित है। अन्य सभी वनौषधियों के रसों को आयुर्वेद के अंतर्गत माना गया है। आयुर्वेद (वैदिक काल का) भी मनुष्य को शरीर के विवेकपूर्ण उपयोग का ही परामर्श देता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है। ऐसी सारी वनौषधियों को रसाहार के अंतर्गत उपयोग में लाना चाहिए, जिनकी पत्तियों के औषधीय उपयोग हैं।

प्रश्न - कौन-कौन से रसाहार सामान्यत: लोगों के काम आते हैं ?

- गेंहू के जवारे, गिलोए, ग्वारपाठा, शीषम, पीपल, अदरक, कड़वी नीम, मीठी नीम, बेलपत्र, अडूसा, अपामार्ग, गेंदे के फूल या पौधे की पत्तियां, हरसिंगार, पोदीना, पान, अगिया, पर्णबीज, मुलेठी, हल्दी, आंवला, मकोय, सहिजन, मेथी, मूली, पालक, टमाटर, मेंथा, गुड़मार, तुलसी, निर्गुण्डी, अमलतास, हड़जोड़, जामुन आदि।

प्रश्न - यह कैसे जानें कि किस मौसम में कौन सा रस लेना चाहिए ?

- सामान्यत: जो पेड़-पौधे जिस मौसम में आसानी से उपलब्ध होते हैं, उसी मौसम में मानव शरीर को उसकी आवश्यकता भी होती है। जैसे आंवला अष्टमी आते ही इसका उपयोग शुरू हो जाता है। जब तक ताजे आंवले मिलते रहें, तब तक उसका उपयोग करें, फिर आंवले के चूर्ण का उपयोग करें। छट पूजा के बाद कच्ची हल्दी का उपयोग होता है। उसे वसन्त पंचमी या अधिक-से-अधिक होली तक उपयोग में ला सकते हैं। भुई आंवला वर्षा ऋतु में अधिक आता है और उसी समय लिवर सम्बन्धी रोग भी अधिक होते हैं। कुछ औषधीय रस ऐसे होते हैं, जो बारहों महीने उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे ग्वारपाठा, गेंहू के जवारे, नारियल पानी इत्यादि।

प्रश्न - पत्तियों का उपयोग कितनी मात्रा में हो?

- आवश्यकतानुसार 5 से 50 पत्तियां। उदारहण के लिए पोदीना, तुलसी, कड़वी नीम, मीठी नीम आदि की 25 से 50 पत्तियां लेते हैं, क्योंकि ये छोटी होती हैं। पीपल, अडूसा जैसे बड़े पत्ते 5 से 10 लिए जाते हैं। भुई व आंवले के पौधे जड़ समेत उखाड़ कर 5 से 10 पौधे लेना चाहिए। गेंहू के जवारे 100 ग्राम एक जन की एक दिन की मात्रा होती है। आंवले 4 या 5 लेने पर 50 मि.ली. रस बन जाता है। हल्दी का रस 25 मि.ली., अदरक या लहसून का रस 2 चम्मच, गिलोए का तना 8 से 9 इंच लम्बा और ग्वारपाठे की पत्तियां छीलकर अंदर का गुदा हाफ कप 50 मि.ली. के बराबर होता है।

प्रश्न - पत्तियों को उपयोग में लाने का क्या तरीका है?

- पत्तियों को उपयोग में लाने से पहले उसे 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लें। पूरा पानी निथारने के बाद आदर्श तरीका तो यह है कि सिलबट्टे पर पत्तियां पीसकर आवश्यकतानुसार पानी डालकर छान कर उसका रस निकाल लें। लेकिन आजकल मिक्सरों से रस निकाला जाता है।

प्रश्न - रस बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पानी कैसा हो?

- रस बनाने के लिए हमेशा उबला हुआ पानी उपयोग में लाएं। यदि एक रात पहले पानी उबाल कर साफ धुले तांबे के बर्तन में रखकर उसे रात भर चुम्बकित कर लें तो और भी अच्छा होगा।

प्रश्न - कौन सा समय रसाहार के लिए अच्छा है?

- रसाहर का सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच का है। शरीर उसी समय स्वाभाविक रूप से मल का त्याग करता है। उसी समय शरीर में पोषक रस भी पहुंचाए जाने चाहिए। इससे पाचन भी सरलता से होते हैं और क्षारीय होने के कारण ये रक्त की पीएच सही बनाए रखते हैं।

प्रश्न - रसाहर के पहले और बाद में खान-पान के क्या नियम हैं?

- रसाहार के पहले एकदम खाली पेट रहना चाहिए। सुबह पानी में नींबू निचोड़ कर ले सकते हैं। चाय के बिना न रह सकें तो काली चाय पी सकते हैं। रसों के पाचन का समय आधा या 2 घंटे का होता है। सभी फलों और पत्तियों के रस आधे घंटे में पच जाते हैं, जबकि सब्जियों के रसों को पचने में 2 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक रस के पीने के बाद उनके पाचन का समय उन्हें अवश्य मिलना चाहिए, तभी उनके पूरे लाभ लिए जा सकते हैं।

प्रश्न - क्या रसाहार शुरू करने के बाद दूसरे औषधियों का उपयोग छोड़ दें?

- रसाहार शुरू करने के बाद सभी विटामिन की गोलियां लेनी बन्द कर देना चाहिए। दर्द निवारक और तीव्र रोगों को दबाने वाली औषधियां अत्यावश्यक हो तो ही लें। जीर्ण रोगों से संबंधित औषधियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायरायड अथवा अन्य अंत:स्त्रावी ग्रन्थियों के रोगों संबंधी औषधियां यथावत लेते रहें।

प्रश्न - रस का स्वाद ठीक न लगे तो उसमें क्या मिलाना चाहिए?

- रस को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें आंवला, नींबू, काली मिर्च, शहद मिला सकते हैं। नमक या कोई अन्य मसालों का उपयोग अथवा दूध व दही आदि उसमें न मिलाएं।

प्रश्न - रस बनाने के बाद कितनी देर तक उसका उपयोग उचित होगा?

- किसी भी रस को बनाए जाने के दो घंटे के भीतर उन्हें पी लेना चाहिए, क्योंकि बाद में उनके गुण कम हो जाते हैं। फल अथवा गेहूं के जवारे के रस के तो 6 घंटे बाद ही खराब होने की संभावना रहती है। अन्य रस भी 24 घंटे बाद खराब हो सकते हैं। गिलोए, ग्वारपाठा, आंवला, तुलसी आदि कुछ रस 24 घंटे फ्रिज में रखे जा सकते हैं।

प्रश्न - रसाहार का नियमित उपयोग कब नहीं करना चाहिए?

- शरीर की अत्यंत जीर्ण अवस्था में रोगी को एकदम से पूरी की पूरी मात्रा का रस नहीं देना चाहिए। प्रतिदिन आधी मात्रा से धीरे-धीरे रोगी को रस देना शुरू कर सकते हैं। 10 दिनों बाद आवश्यकतानुसार रसो की संख्या बढ़ाई जा सकती है। छोटे बच्चों के साथ भी यही नियम है।

प्रश्न - रसाहार के लाभ कितने दिनों में दिखाई देने लगते हैं?

- शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में नई लाल रक्त कणिकाएं बनने में चार महीने का समय लगता है। आयुर्वेद में भी औषधीय प्रभावों के 40 दिन, 4 माह या सवा साल में दिखाई देने के उदाहरण मिलते हैं। मेरा अनुभव भी यही कहता है कि रसाहार प्रारंभ करते ही 8-10 दिनों में पाचन तंत्र में परिवर्तन अनुभूत होने लगते हैं, लेकिन रोग पर होने वाला वास्तविक प्रभाव 4 माह में ही दिखाई देता है। जीर्ण रोगों के ठीक होने का एक सामान्य नियम है कि रोग जितना पुराना है, ठीक होने में उससे दोगुना समय लगता है।

प्रश्न - रसाहार से कौन-कौन से रोगों को ठीक किया जा सकता है?

रोग चाहे कोई भी हो, उनके कारण निश्चित है। हमारी विवेकहीन दिनचर्या, अपने शारीरिक अंगों का आवश्यकता से अधिक या कम उपयोग, वंशानुगत रोग, तनाव, पोषक तत्वों की कमी और इन सब के कारण शरीर में होने वाला विजातीय तत्वों का जमावड़ा। रसाहार से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, वात, पित्त, कफ का संतुलन होता है, शरीर का शोधन होता है, विजातीय तत्व शरीर से निकाल बाहर किए जाते हैं और शरीर निर्मल हो जाता है। इसलिए रसाहार के साथ योग और विवेकपूर्ण दिनचर्या हो तो अंगों की स्थाई विकृति को छोड़कर सभी रोग ठीक किए जा सकते हैं। धीरज के साथ रसाहार के प्रयोग की बराबरी किसी पैथी में नहीं है।

- सुदीप सिन्हा

जिंदादिल लोगों के
जांबाज अखबार
जासूस बादशाह को
मकर संक्रांति
के अवसर पर
हार्दिक शुभकामनाएं।
एक शुभेच्छु

निर्माण माफिया पर सरकार ने कसा शिकंजा

भोपाल। भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार बरसों से लंबित कड़वे फैसले लेना आरंभ कर दिए हैं। अधोसंरचना विकास के नाम पर पनपे निर्माण माफिया पर शिकंजा कसने के लिए शासन ने टेंडर और निविदाएं बुलाने का तरीका ही बदल दिया है। इससे निर्माण के क्षेत्र में बरसों से मोटी मलाई काट रहे माफिया और उसके गुर्गे तो हताश हुए ही हैं साथ में वे अखबार वाले भी नाराज हो गए हैं जिन्हें इस नीति से खासा राजस्व प्राप्त होता रहा है।

निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों केआला अफसर जब अपने कार्यों को अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए तरीके खोज रहे थे तब उनकी निगाह निर्माण माफिया की गतिविधियों पर पहुंची थीं। उन्होंने पाया कि निर्माण माफिया खुली प्रतिस्पर्धा से तो अच्छी कंपनियों को बाहर करवा देते हैं फिर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ एसा माहौल बना देते हैं जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है साथ में सरकारी खजाने से निकाली जाने वाली रकम का अपव्यय अधिक होता है।

प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने इस निर्माण माफिया पर लगाम लगाने के लिए अपनी टेंडर नोटिस वाली प्रणाली को बदलने का फैसला लिया। लोक निर्माण विभाग के सचिव की ओर से जारी पत्र क्रमांक एफ 53 / 16 / 2012 / 19 / भो.4067 भोपाल दिनांक 01.07.2013 जो सभी निर्माण विभागों को भेजा गया था उस पर चुनाव होने तक कोई गौर नहीं कर पाया लेकिन जब इस पत्र पर अमल शुरु हुआ तब निर्माण माफिया को समझ में आया कि इस तरह तो वह मैदान से बाहर ही धकेल दिया जाएगा। नतीजतन उनसे शासन की इस नीति को बदलवाने के लिए दबाव बनाना शुरु कर दिया। इस दबाव को कारगर बनाने के लिए नीति के उस भाग को रेखांकित किया गया जिसमें लघु दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापनों दिए जाने पर अंकुश लगाया गया था।

शासन के इस पत्र की इबारत समझ में आने पर लघु दैनिक समाचार पत्रों के मालिकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट करके अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहकर मामले को टाल दिया कि वे दस्तावेजों में उठाई गई परेशानी को पढ़ समझकर कोई फैसला लेंगे।

लघु एवं मध्यम समाचार पत्र एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री महोदय के अलावा मुख्य सचिव एंटोनी डिसा और मुख्यमंत्री के सचिव मनोज श्रीवास्तव से भेंट करके भी उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में लघु दैनिक समाचार पत्रों के मालिकों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने इस पत्र के माध्यम से केवल कुछ विशिष्ट श्रेणी के समाचार पत्रों को ही विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। यहआदेश लघु एवं मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों के हितों पर कुठारघात कर रहा है। इससे प्रदेश के पांच बड़े अखबारों को तो विज्ञापन मिल रहे हैं लेकिन छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को भारी क्षति पहुंच रही है। एक तरह से ये कदम सेंसरशिप के समान है और इससे छोटे अखबारों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि श्रेणी क्रमाक एक के अनुसार एक से दो करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के विज्ञापन संभागीय मुख्यालय से प्रकाशित केवल एक या दो अखबारों को ही मिल पाएंगे। यह नीति पूरी तरह अवैज्ञानिक है। इससे केवल पांच समाचार पत्रों को ही विज्ञापन मिल सकेंगे। संभागों और जिलों के मुख्यालयों या अन्य स्थानों से प्रकाशित अखबार तो इस दौड़ में टिक नहीं सकते। बड़े समाचार पत्रों में चालीस फीसदी से ज्यादा विज्ञापन जारी करके, ये संस्थान विज्ञापन नीति का उल्लंघन कर रहे हैं।

दूसरी श्रेणी में दो करोड़ से लेकर दस करोड़ तक की निविदा राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों को देने के आदेश जारी हुए हैं। ये विज्ञापन पांच बड़े समाचार पत्रों को जारी होंगे जिसमें से एक भोपाल से प्रकाशित और एक संभागीय मुख्यालय से प्रकाशित अखबार होगा। जाहिर है कि इससे प्रदेश के अन्य स्थानों से प्रकाशित अखबारों को कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा। जबकि आज कोई भी अखबार राज्य स्तरीय नहीं रह गया है। हर संभाग और जिलों में एक ही शीर्षक से प्रकाशित अखबार अलग अलग संस्करणों के रूप में प्रकाशित होते हैं। सारे अखबार कई अलग अलग स्थानों से मुद्रित होते हैं।

दस करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों की निविदाएं तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों जिनमें से एक अंग्रेजी और दो हिंदी के समाचार पत्र होंगे उनमें जारी की जाएंगी। जबकि आज राष्ट्रीय अखबार भी अलग अलग प्रदेशों से प्रकाशित हो रहे हैं। जाहिर है कि मध्यप्रदेश में प्रकाशित राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन जारी करने से राष्ट्रीय स्तर के ठेकेदार इस प्रतिस्पर्धा में कैसे भाग ले सकेंगे।

छोटेऔर मध्यम दैनिक समाचार पत्रों की ये परेशानी वाजिब भी है लेकिन सरकार के इस फैसले से निविदाओं की सूचना व्यापक दायरे तक पहुंच पाने की राह प्रशस्त हो रही है। तकनीकी क्रांति से जहां विज्ञापन वेवसाईट पर आसानी से जारी किए जा सकते हैं वहीं देश विदेश की निर्माण एजेंसियों तक उनकी पहुंच भी सटीक होती जा रही है। इन हालात में संभव है कि शासन अपनी नीति में और भी नए सुधार लागू करे। जहां तक छोटे समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन जारी करने की बात है तो ये सरकार के लिए नया सिरदर्द जरूर साबित हो सकती है।

विकास का लाभ गरीब को मिले:शिवराज सिंह

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में घोषणा की है कि नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत आगामी छह फरवरी को क्षिप्रा में नर्मदा का जल पहुंचेगा। नदी जोड़ो अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था जो मध्यप्रदेश में साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए क्षैज्ञणिक सत्र से पहली कक्षा में ही जाति प्रमाण पत्र देने की योजना लागू की जा रही है। किसानों को प्रेरित करने के लिए खेत तीर्थयोजना लागू की जा रही है। व्यापमं में जिसने भी अपराध किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस संबंध में तत्परता और निष्पक्षता से कार्रवाई की जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के दौरान मुख्यमंत्री ने ये सभी बातें उठाईं।

उन्होंने कहा कि दृष्टिपत्र 2018और जनसंकल्प के एक एक बिंदु को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। संपूर्ण विकसित और समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का काम सबके सहयोग से किया जाएगा। हम प्रदेश के निर्माण और विकास का नया इतिहास लिखेंगे।

उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान करने के लिए काम कर रही सरकार के साथ प्रतिपक्ष रचनात्मक सहयोग करे, तथ्यात्मक गलतियों की ओर ध्यान खींचे ताकि हम सभी मिल जुलकर नया मध्यप्रदेश बना सकें।

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. Jasoos1967@yahoo.com